प्रदेश में उद्योगों की रफ्तार दोगुनी

यूपीसीडा ने बनाया रिकॉर्ड, पहली बार प्राधिकरण की आय 1300 करोड़ के पार

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। औद्योगिक विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लागू नीतियों का असर दिखने लगा है। बेहतर उद्योग नीतियों की वजह से पहली बार यूपीसीडा ने रिकॉर्ड बनाते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1359 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग राजस्व प्राप्त किया है। ये राजस्व कोविड से पूर्व वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में दोगुना है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था दस खरब डालर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 25 से ज्यादा सेक्टोरल पॉलिसी बनाई हैं। इन पालिसी के जरिये सेक्टरवार इकाइयों की मदद की जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। प्रदेश में अधिक से अधिक औद्योगीकरण के लिए यूपीसीडा ने भूमि बैंक का विस्तार करने के लिए लैंड ऑडिट किया। विभिन्न

34 सेवाओं को डिजिटल करने का दिखा असर

नीतिगत सुधारों जैसे एफएआर में बदलाव और विभाजन का सरलीकरण आदि के माध्यम से अप्रयुक्त भूमि का बेहतर इस्तेमाल किया। उद्योग हित में जमीन की वैल्यू अनलॉकिंग की गई।

ई ऑक्शन और निवेश मित्र से बदली तस्वीर : राज्य सरकार के प्रयासों के तहत सबसे महत्वपूर्ण ई ऑक्शन और निवेश मित्र पर पारदर्शी जमीन आवंटन किया। इसका परिणाम ये हुआ कि पिछले तीन वर्षों में निवेशकों को रिकॉर्ड संख्या में 1600 से अधिक प्लॉटों का आवंटन हुआ, जिसने उत्तर प्रदेश को देश के औद्योगिक विकास का इंजन बनाने में मदद की है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में डिजिटलीकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यूपीसीडा निवेश मित्र के माध्यम से वर्तमान में 34 ऑनलाइन ई-सेवाएं दे रहा है, जो कोविड काल से पहले मात्र दो थीं। परिणामस्वरूप 31,000 से अधिक आवेदनों का 96 फीसदी संतुष्टि दर के साथ निस्तारण किया गया है।

औद्योगिक इलाकों में पहली बार महिलाओं पर फोकस करतीं योजनाएं

कौशल विकास को बढ़ावा देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने लिए प्राधिकरण ने अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन (एआईआईएम) और सुरक्षित औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाओं की पहल की है। इसके तहत क्रेच, पिंक शौचालय और पिंक डोरमैट्री जैसी महिला केंद्रित सुविधाओं का विकास औद्योगिक क्षेत्रों में किया गया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप औद्योगिक पार्कों में महिला भागीदारी और रोजगार में वृद्धि हुई है। इन प्रयासों से एक तरफ जहां प्राधिकरण की आय बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक खर्चों में वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में नौ प्रतिशत की कटौती भी की गई है। यूपीसीडा ने निवेशकों की सुविधा हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रचर के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे यूपीसीडा के अवस्थापना विकास व्यय में चार गुना वृद्धि हुई है। यह वित्त वर्ष 2017-18 में 104 करोड़ से बढ़ कर 415 करोड़ हो गया।

निवेशकों को मिला लाभ

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए-नए काम किए जा रहे हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। अकेले वर्ष 2023-24 में ही 693 प्लाटों का आवंटन किया गया। इससे एक तरफ निवेशकों को लाभ मिला तो दूसरी तरफ प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई।

- मयूर महेश्वरी,
सीईओ, यूपीसीडा